



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, ४ फरवरी, १९९८/१५ मार्च, १९१९

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-२, ४ फरवरी, १९९८

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)-२/९७.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक ३-२-१९९८ को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 19) को 1998 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

1998 का अधिनियम संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 3 फरवरी, 1998 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं में बालक-बालिकाओं की अनिवार्य उपस्थिति से सम्बन्धित विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठ्ठालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1997 है।

संक्षिप्त नाम
और
विस्तार।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

परिभाषाएं

- (क) “नियत दिन” से प्रथम अप्रैल, 1998 अभिप्रेत है;
- (ख) “बालक-बालिका” से ऐसा/ऐसी बालक/बालिका अभिप्रेत है जिसकी आयु छह वर्ष से कम न हो और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो;
- (ग) “सरकारी पाठशाला” से राज्य सरकार द्वारा स्थापित और पोषित पाठशाला अभिप्रेत है;
- (घ) “स्थानीय प्राधिकरण” से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पंचायत, नगर परिषद् या नगर निगम अभिप्रेत है;
- (ङ) “माता-पिता” के अन्तर्गत अभिभावक या अन्य ऐसा व्यक्ति भी है, जिसकी वास्तविक अभिरक्षा में या जिसके संरक्षण में बालक/बालिका हो;
- (च) “प्राथमिक शिक्षा” से पढ़ाई, लिखाई और गणित के सम्बन्ध में ऐसी शिक्षा जो राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक पाठशालाओं के स्तर के लिए यथा-विहित की जाए और अन्य विषयों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में ऐसी शिक्षा जोकि राज्य सरकार द्वारा या विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से स्थानीय प्राधिकरण नियत करे, अभिप्रेत है;
- (छ) “प्राथमिक पाठशाला” से ऐसी पाठशाला अभिप्रेत है जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती है;
- (ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) “विहित प्राधिकारी” से ऐसा प्राधिकारी जो कि सामान्यतः या विशेष प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिसूचित किया गया हो, अभिप्रेत है;
- (ञ) “पाठशाला समिति” से इस अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त समिति अभिप्रेत है;
- (ट) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (ठ) “किसी प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित होना” से विहित प्राधिकारी द्वारा नियत पाठशाला में, वर्ष के नियत दिनों, नियत समय या समयों और उपस्थिति के प्रत्येक दिन में नियत घंटों के लिए, शिक्षण के लिए उपस्थित होना, अभिप्रेत है;

अनिवार्य
प्राथमिक
शिक्षा।

3. राज्य में नियत तारीख से प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी।

पाठशाला
समिति की
नियुक्ति।

4. (1) विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन पाठशाला समिति के कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिए एक या अधिक समितियाँ नियुक्त करेगा।

(2) पाठशाला समिति की संरचना, इसके सदस्यों के नाम-निर्देशन और उनके हटाए जाने की प्रक्रिया, उनकी पदावधि, उनके ऐसे सदस्य क रूप में बने रहने की अर्हताएं और निरर्हताएं, रिक्तियों का भरना, पाठशाला समिति का विघटन और इसके कारबार के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन, पाठशाला समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:—

- (क) अपने क्षेत्र में बालक-बालिकाओं और उनके माता-पिता में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का प्रचार करना;
- (ख) अपने क्षेत्र में, पाठशालाओं में कार्य समय, अवकाश और प्रावकाश में, परिवर्तन की सिफारिश करना जो पाठशाला समिति को आवश्यक प्रतीत होते हों;
- (ग) ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना और दोपहर के भोजन की स्कीम सहित ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना जो कि अपने क्षेत्र में पाठशालाओं में उपस्थित होने वाले बालक-बालिकाओं के लिए विहित की जाएं;
- (घ) इस अधिनियम के अधीन पाठशालाओं में अनिवार्य उपस्थिति से छूटों की सिफारिश करना;
- (ङ) अपने क्षेत्र की पाठशाला में उपस्थित होने के लिए उत्तरदायी बालक-बालिकाओं की अद्यतन सूची रखना और ऐसी अन्य सूचना एकत्रित करना और उसका अभिलेख रखना जो पाठशाला में बालक-बालिकाओं को उपस्थित कराने और ऐसी उपस्थिति में बाधा डालने को निवारित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;
- (च) अपने क्षेत्र की पाठशालाओं में तैनात प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों की और अध्यापनेत्तर कर्मचारीवृन्द की उनकी, देर से आने या अनुपस्थिति के मामलों की रिपोर्ट करना;
- (छ) अपने क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के कार्य में रत सरकारी पद-धारियों को आवश्यक सहायता देना।

बालक-
बालिकाओं
को पाठशाला
में उपस्थित
करवाने का
माता-पिता
का कर्तव्य।

5. प्रत्येक बालक-बालिका के माता-पिता, यदि ऐसा बालक-बालिका साधारणतया राज्य में निवास करता है, व्यक्तिगत्त कारण न होने पर, ऐसे बालक-बालिका को प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित करवाएगा।

6. जहाँ पाठशाला समिति का यह समाधान हो जाता है कि धारा 5 के उप-बन्धों के अधीन बालक-बालिका को प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित करवाने के लिए बाध्य कोई माता-पिता ऐसा करने में असफल रहा है, तो पाठशाला समिति, माता-पिता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझती है, माता-पिता को ऐसे बालक-बालिका को उस तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएगी, प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित करवाने के लिए निर्देशित करते हुए आदेश दे सकेगी।

पाठशाला समिति द्वारा उपस्थिति आदेश जारी किया जाता।

7. (1) कोई माता-पिता जिनके विरुद्ध धारा 6 के अधीन आदेश पारित किया गया है, और जो, युक्तियुक्त कारण के बिना, ऐसे आदेश का पालन करने में असफल रहा है, मैजिस्ट्रेट या ग्राम पंचायत के समक्ष दोषसिद्धि पर, दो सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

उपस्थिति आदेश का पालन करने में असफल रहने पर शास्ति।

(2) कोई माता-पिता जो उप-धारा (1) के अधीन अपराध के लिए सिद्धोष ठहराए जाने पर, धारा 6 के अधीन पारित आदेश की अवज्ञा करना जारी रखता है, वह अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन, जिसके दौरान उस द्वारा आदेश की लगातार अवज्ञा किया जाना साबित हो जाए, के लिए पांच रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

8. कोई व्यक्ति जो, पाठशाला में उपस्थिति के लिए विहित समय के दौरान, स्वयं अपनी ओर से, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी नियोजन के सम्बन्ध में, चाहे पारिश्रमिक के लिए या उसके बिना, किसी बालक-बालिका जिसके माता-पिता, इस अधिनियम के अधीन उसे प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित करवाने के लिए अपेक्षित हैं, की सेवाओं का उपयोग करता है, वह मैजिस्ट्रेट या ग्राम पंचायत के समक्ष दोषसिद्धि पर, पांच सौ रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

प्राथमिक पाठशाला में उपस्थित होने के लिए उत्तरदायी बालक-बालिका को नियोजित करने के लिए शास्ति।

9. कोई भी न्यायालय धारा 7 या धारा 8 के अधीन अपराध का संज्ञान, पाठशाला समिति, या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे पाठशाला समिति द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया जाए, की शिकायत पर या से प्राप्त सूचना के सिवाए, न करेगा।

अपराधों का संज्ञान।

10. राज्य सरकार, राज्य में प्राथमिक शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करेगी।

राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उपबन्ध।

11. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।

(2) विशिष्टता और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी:—

- (क) धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षण-क्रम विहित करना;
- (ख) साधारणतः अवधारित करना कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए किसे पर्याप्त उपबन्ध समझा जाए;
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में बालक-बालिकाओं का रजिस्टर तैयार करना और प्रकाशित करने की अपेक्षा करना;
- (घ) वह रीति, जिसमें पाठशाला समिति गठित की जाए, इसके सदस्यों का नामनिर्देशन और हटाए जाने की प्रक्रिया तथा उनकी अर्हताएं और निरर्हताएं, कर्तव्य, शक्ति और उत्तरदायित्व;
- (ङ) पाठशाला में बालकों-बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पाठशाला समिति द्वारा उठाए जाने वाले पग और वे शर्तें जिनके अधीन पाठशाला से अनुपस्थिति से छुट्टी अनुज्ञात की जा सकेगी;
- (च) प्रत्येक पाठशाला समिति की अधिकारिता, जहां एक से अधिक पाठशाला समितियां नियुक्त की जाती हैं;
- (छ) पाठशाला समिति और किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी शिक्षा समिति, जो किसी अन्य अधिनियम के अधीन नियुक्त की जाए, के बीच रखे जाने वाले सम्बन्ध; और
- (ज) विहित किए गए या किए जा सकने वाले विषय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने या जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा, और यदि उस सत्र या अगामी सत्र के अवसान से पूर्व जिसमें, यह ऐसे रखा गया था, विधान सभा किसी ऐसे नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करती है या विधान सभा विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तत्पश्चात्, नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु ऐसा कोई उपान्तरण या वातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या करने से छोड़ दी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

निरसन और
व्यावृत्तियां।

12. (1) हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1953 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

1954 का
7.

(2) ऐसे निरसन के होने हुए भी, ऐसे निरसित किए गए अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उसी तारीख को प्रवृत्त था जिसको ऐसी बात या कार्यवाई की गई थी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 1998.

**THE HIMACHAL PRADESH COMPULSORY PRIMARY
EDUCATION ACT, 1997**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD FEBRUARY, 1998)

AN

ACT

to re-enact the law relating to the compulsory attendance of children in primary schools in Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Act, 1997. Short title and extent.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

(a) “appointed day” means the 1st day of April, 1998;

(b) “child” means child whose age is not less than six, and not more than eleven years;

(c) “Government school” means a school established and maintained by the State Government;

(d) “local authority” means a Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation;

(e) “parent” includes guardian or any person who has the actual custody or is in charge of a child;

(f) “primary education” means such instruction in reading, writing and arithmetic, as may be prescribed for the time being at the primary school level by the State Government and such instruction in other subjects, if any, as may be determined by the State Government or the local authority with the approval of the prescribed authority;

(g) “primary school” means a school in which instruction in primary education is given;

(h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

(i) “prescribed authority” means an authority notified as such by the State Government whether generally or for a particular purpose;

(j) “school committee” means a committee appointed under the provisions of section 4 of this Act;

(k) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh; and

(l) “to attend a primary school” means to be present for instruction at such school, on such days in the year, at such times or time and for so many hours on each day of attendance, as may be fixed by the prescribed authorities.

3. From the appointed day the primary education of children shall be compulsory in the State. Compulsory primary education.

Appointment of a school committee.

4. (1) The prescribed authority shall appoint one or more committees for the purpose of exercising the powers and performing the duties of the school committee under this Act.

(2) The composition of the school committee, the procedure of nomination and removal of its members, their term of office, their qualifications and disqualifications for continuing as members, the filling of vacancies, the dissolution of the school committee and the procedure for the conduct of its business, shall be such as may be prescribed.

(3) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the school committee shall exercise and discharge the following powers and functions, namely:—

- (a) to propagate the spread of primary education among the children and parents in its area;
- (b) to recommend any changes which may seem to the school committee to be necessary in the hours of work, holidays and vacations in the schools in its area ;
- (c) to make arrangements to provide such facilities and to supervise the implementation of such schemes including mid-day meal scheme, as may be prescribed to the children attending schools in its area;
- (d) to recommend exemptions from compulsory attendance at schools under this Act;
- (e) to maintain an up-to-date list of children liable to attend school in its area and to obtain and keep record of such other information as may be necessary for the purpose of enforcing the attendance of children at school and of preventing interference with such attendance;
- (f) to report the cases of absence of late attendance of primary school teachers and non-teaching staff posted in schools in its area; and
- (g) to render all necessary help to Government officials engaged in the work of compulsory primary education in its area.

Duty of parents to cause children to attend school.

5. The parents of every child, shall, if such child ordinarily resides in the State, in the absence of a reasonable excuse, cause such child to attend primary school.

Issue of attendance order by the school committee.

6. Where the school committee is satisfied that a parent who is bound under the provisions of section 5 to cause the child to attend a primary school, has failed to do so, the school committee may, after giving the parent an opportunity of being heard, and after such inquiry as it considers necessary, pass an order directing the parent to cause child to attend a primary school from a date which shall be specified in the order.

Penalty for failure to obey attendance order.

7. (1) Any parent against whom an order has been passed under section 6 and who, without reasonable excuse has failed to obey such order, shall on conviction before a Magistrate or a Gram Panchayat, liable to a fine not exceeding two hundred rupees.

(2) Any parent who having been convicted for an offence under

sub-section (1) continues to disobey the order passed under section 6 shall be liable to further fine which may extend to five rupees, for every day after the date of the first conviction during which he has been proved to have persisted in disobeying the order.

8. Any person who shall, during the prescribed hours of attendance at a school, utilize on his own behalf or on behalf of any other person, in connection with any employment, whether for remuneration or not, the services of any child whose parent is required under the Act to cause him to attend a primary school, shall, on conviction before a Magistrate or a Gram Panchayat be liable to a fine not exceeding rupees five hundred.

Penalty for employing child liable to attend primary school.

9. No court shall take cognizance of an offence under section 7 or section 8 except on the complaint of or on information received from the school committee, or from such person as may be authorised by the school committee or by the State Government by general or special order in this behalf.

Cognizance of offences.

10. The State Government shall make facilities for primary education available in the State.

Provision of primary education by the State Government.

11. (1) The State Government may, after previous publication, make rules for the purpose of this Act.

Power of State Government to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the State Government may make rules,—

- (a) prescribing under clause (f) of section 2 the range of instruction in primary schools ;
- (b) determining generally what shall be considered to be adequate provision for compulsory primary education;
- (c) requiring the local authority to prepare and publish a register of children in its area ;
- (d) the manner in which the committees shall be constituted, the procedure of nomination and removal of its members and their qualification and disqualification, duties, power and responsibility;
- (e) the steps which the school committee may take to secure attendance of children at school and the conditions under which leave of absence from school may be allowed;
- (f) the jurisdiction of each school committee where more than one school committees are appointed;
- (g) the relations to be observed between the school committees and any education committee of any local authority that may have been appointed under any other Act; and
- (h) the matters which are to be and may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act, shall as soon as possible, after it is made or issued, be laid on the Table of the Legislative Assembly and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the next session, the Assembly

makes any modification in any such rule or notification or the Assembly decides that rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule.

Repeal
and
savings

12. (1) The Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Act, 1953 is hereby repealed.

7 of 1954

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, as if, this Act was in force on such date on which such thing was done or action was taken.